साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 20-26 मई 2024 वर्ष-10, अंक-5

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

भोपाल और इंदौर में 20 जून तक आएगा मानसून

तरबतर होगा मध्यप्रदेश

» एक दिन पहले 31 मई को केरल में देगा दस्तक

» सीजन में 104 प्रतिशत तक बारिश की संभावना

भोपाल। जागत गांव हमार

बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि झेल रहे मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी खुशखबरी आई है। इस बार देश में मानसून तय समय से एक दिन पहले 31 को केरल में दस्तक दे सकता है। 28 मई से 3 जून के बीच कभी भी मानसूनी बारिश झमाझम शुरू हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह खुशखबरी दी है। देश में 1 जून से 30 सितंबर तक मानसूनी सीजन में 104 प्रतिशत बारिश की संभावना जताई है। इस बीच, मध्यप्रदेश को भी खुशखबरी मिली है। प्रदेश में औसत 106न बारिश का अनुमान जताया गया है। राजधानी भोपाल और इंदौर संभाग में 20 जून को मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस बार मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 17 या 18 जून को मध्यप्रदेश में प्रवेश कर सकता है। इसके बाद 20 जून को भोपाल और इंदौर में पहली मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी।

राज्य में कब मानसून की एंट्री

राज्य	तारिख		
केरल	01 से 3 जून	गोवा	05 जून
तमिलनाडु	01 से 5 जून	ओडिशा	11 से 16 जून
आंध्र प्रदेश	04 से 11 जून	चंडीगढ़	28 जून
कर्नाटक	03 से 8 जून	दिल्ली	27 जून
बिहार	13 से 18 जून	उत्तर प्रदेश	18 से 25 जून
झारखंड	13 से 17 जून	हरियाणा	27 जून से 3 जुलाई
वेस्ट बंगाल	07 से 13 जून	हिमाचल प्रदेश	22 जून
छत्तीसगढ़	13 से 17 जून	जम्मू-कश्मीर	22 से 29 जून
गुजरात	19 से 30 जून	उत्तराखंड	20 से 28 जून
मध्य प्रदेश	16 से 21 जून	पंजाब	26 जून से 1 जुलाई
महाराष्ट्र	09 से 16 जून	राजस्थान	25 जून से 6 जुलाई

चार संभागों में कम बारिश

प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, चंबल संभागों में सामान से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। यहां 104 से 106 प्रतिशत तक बारिश हो सकती है। वहीं, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर संभाग में कम बारिश होने का आसार नजर आ रहे हैं। पूरे प्रदेश की स्थिति देखी जाए तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में 100 प्रतिशत बारिश की संभावना है।

किसानों के लिए अच्छी खबर

पिछले साल, मानसून 96 परसेंट की सामान्य बारिश के मुकाबले 94.4 परसेंट पर सामान्य से नीचे था। कम बारिश के कारण महाराष्ट्र के कई हिस्सों में इस समय सूखे के हालात हैं। राज्य में पीने के पानी से लेकर खेती के पानी तक पानी की भारी कमी है। अधिक बारिश किसानों के लिए अच्छी खबर है।

किसान व्यापारियों को गेहूं बेचना पसंद कर रहे

समर्थन पर गेहूं खरीद के लक्ष्य से दूर एमपी-राजस्थान सरकार

» मप्र में 47 लाख मीट्रिक टन की खरीद, लक्ष्य 80 लाख टन का

» अधिकांश सूबों की उपज मंडियों में आवक बंद

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

एमएसपी पर गेहूं खरीद की वर्तमान रफ्तार को देखते हुए इस साल भी सरकारी टारगेट पूरा होने की उम्मीद नहीं है। केंद्र सरकार ने इस साल 372.9 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा हुआ है, जबकि अभी तक महज 257 लाख मीट्रिक टन की ही खरीद हो सकी है। ऐसे में इस साल ओपन मार्केट सेल स्कीम को लागू होने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। अब अधिकांश सूबों की मंडियों में आवक बंद हो गई है। किसान सरकार की बजाय व्यापारियों को गेहूं बेचना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ओपन मार्केट में दाम अच्छा मिल रहा है। यहां तक कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में एमएसपी पर बोनस मिलने के बावजूद खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में गेहूं बेचने पर किसानों को 125 रुपए क्विंटल का बोनस मिल रहा है। इस समय गेहूं की एमएसपी 2275 रुपए क्विंटल है। यानी इन दोनों सूबों में किसानों को 2400 रुपए का भाव मिल रहा है। इसके बावजूद दोनों

खरीद के मामले में पिछड़े हुए हैं। राजस्थान में 20 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि अब तक मात्र 8,56,331 मीट्रिक टन की ही खरीद हो पाई है। इसी तरह मध्य प्रदेश में सिर्फ 47 लाख मीट्रिक टन की खरीद हो सकी है, जबकि लक्ष्य 80 लाख टन का है।

यूपी में रिकॉर्ड तोड़ खरीदी

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। देश का लगभग 35 फीसदी गेहूं यहीं पैदा होता है। राज्य में अब तक 8,69,852 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो गई है, जो पिछले तीन साल में सबसे ज्यादा है। रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 के दौरान उत्तर प्रदेश में 3.29 लाख मीट्रिक टन गेहूं ही खरीदा जा सका था। जबकि 2023-24 में खरीद इससे भी कम हो गई थी। तब सिर्फ 2,19,797 मीट्रिक टन गेहूं की ही एमएसपी पर खरीद हुई।

कृषि विश्वविद्यालयों के काम को प्रभावी बनाने की तैयारी

खेती के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालय सीधे देंगे फंड!

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्रीय कृषि मंत्रालय खेती से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) को सीधे फंड देने की तैयारी कर रहा है। यह काम अब तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के माध्यम से किया जाता रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि अगर एक कृषि विवि कुछ शोध कार्य कर रहा है, तो अन्य राज्यों के अन्य कृषि विश्वविद्यालयों को भी इसके बारे में पता नहीं चलता है। कभी-कभी तो एक ही राज्य के भीतर भी किसी को यह नहीं पता होता है कि दूसरा विश्वविद्यालय क्या गतिविधियां कर रहा है। ऐसे में बेहतर समन्वय के लिए कृषि मंत्रालय ने पहली बार राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की। जिसमें उन्हें विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में शामिल करने की पेशकश की गई। अब तक यह सब आईसीएआर के माध्यम से होता रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि कृषि और किसान कल्याण विभाग को उस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के बजाय कई योजनाओं के कार्यान्वयन पर बेहतर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां आईसीएआर को काम करने की अनुमति दी गई है। इस बैठक की अध्यक्षता कृषि सचिव मनोज आहूजा ने की। आईसीएआर का प्रमुख बड़ा अधिकारी इस बैठक में मौजूद नहीं था।

बेहतर परिणाम मिलेंगे

अधिकांश कुलपति प्रोजेक्ट के आधार पर सीधे धन प्राप्त करने के खिलाफ नहीं थे। हालांकि वे धन की कमी का सामना कर रहे हैं इसलिए वे सरकार के लिए किसानों के साथ विस्तार गतिविधियों को शुरू करने के इच्छुक नहीं थे। क्योंकि ऐसा मानना है कि इससे शिक्षा प्रदान करने के उनके मुख्य कार्य में बाधा आएगी। सरकार का मानना है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं में अत्यधिक अनुभवी कृषि वैज्ञानिकों की भागीदारी से बेहतर परिणाम मिलेंगे।

राज्यों के अधीन रहेंगे, केंद्र से भी जुड़ेंगे

राज्य कृषि विवि सीधे राज्य सरकार के अधीन आते हैं, इसलिए वो सीधे केंद्र से जुड़कर भी राज्यों को दरकिनार नहीं कर पाएंगे। हालांकि, कृषि और किसान कल्याण विभाग के अधिकारी जिन्होंने एसएयू को शामिल करने का विचार किया था, उनका माननाहै कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां एक साथ काम करने की गुंजाइश है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि एक बेहतर सुझाव है। एसएयू के साथ समन्वय से उन्हें रिसर्च एवं विकास गतिविधियों के दोहराव से बचने और नई तकनीक के विकास की ओर फिर से उन्मुख होने में मदद मिल सकती है। अधिकारियों ने कहा कि विभाग को जो कुछ भी चाहिए, उसके लिए एसएयू के साथ संवाद हमेशा आईसीएआर या राज्य सरकार के माध्यम से नहीं होना चाहिए। वर्तमान में, एसएयू द्वारा विकसित बीजों की कई अच्छी किस्में एक छोटे दायरे तक ही सीमित हैं, जहां एक विशेष एसएयू स्थित है, जबकि ऐसी किस्मों के पूरे देश में फैलने की संभावना है। नई पहल से ऐसा संभव हो सकेगा।

ऊन-दूध नहीं, अब मीट के लिए पाली जा रहीं हैं भेंड़ और बकरियां, दो राज्यों में ऊन का उत्पादन जीरो

भेड़-बकरे ही नहीं, बफैलो मीट का भी देश में बड़ा कारोबार

भेड़-बकरी की इसी खूबी के चलते ही इन्हें अब एटीएम भी कहा जाने लगा

भोपाल। जागत गांव हमार

भेड़ और बकरी दो ऐसे पशु हैं जिनके मीट की मांग उनके ऊन और दूध के मुकाबले कहीं बहुत ज्यादा है। आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। मीट पर जोर देने की वजह से दो राज्यों में ऊन का उत्पादन जीरो हो गया है। एनिमल मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक न सिर्फ घरेलू बाजार बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी कुछ खास नस्ल के भारतीय भेड़-बकरी बहुत पसंद किए जाते हैं। भेड़-बकरी की इसी खूबी के चलते ही इन्हें अब एटीएम भी कहा जाने लगा है। बकरीद का बाजार तो ऐसा है जहां पशुपालक पूरे साल पाले गए बकरों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। बेशक दुनियाभर के देशों में सबसे ज्यादा भैंस का मीट एक्सपोर्ट होता है, लेकिन डिमांड और स्वाद के मामले में बकरे और भेड़ का मीट भी पीछे नहीं है। बेशक इसके महंगा होने के चलते एक्सपोर्ट का आंकड़ा थोड़ा छोटा है, फिर भी दुनिया के 10 बड़े खरीदारों में खाड़ी के छह देश शामिल हैं। कतर में फीफा वर्ल्ड कप के दौरान तो भारत से बड़ी मात्रा में बकरे का मीट एक्सपोर्ट हुआ था। खास बात ये है कि खाड़ी देशों को लाइव बकरे भी बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट होते हैं।

भेड़-बकरे के मीट के आयातक

एपीडा के आंकड़े बताते हैं कि भारत से एक्सपोर्ट होने वाले भेड़-बकरे के मीट के सबसे बड़े खरीदारों में खाड़ी के देश हैं। साल 2022-23 में टॉप-5 आयातक देशों में संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, मालदीव और ओमान शामिल हैं। मीट खरीदने वालों की लिस्ट में बहरीन भी शामिल है। भारत विश्व का भेड़-बकरी के मांस का सबसे बड़ा निर्यातक है। साल 2022-23 के दौरान भारत से 537 करोड़ रुपए के भेड़-बकरे के मीट का एक्सपोर्ट किया था। इस दौरान एक्सपोर्ट किए गए मीट की मात्रा 10 हजार मीट्रिक टन थी। साल 2022-23 में बकरे के मीट का 14.13 लाख टन और भेड़ का 10.26 लाख टन उत्पादन हुआ था।

मीट के लिए सबसे ज्यादा बि कने वाले बकरे

केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान (सीआईआरजी), मथुरा के गोट एक्सपर्ट की मानें तो देश में बकरे और बकरियों की 39 नस्ल हैं। इसमे सात ऐसी नस्ल हैं जो खासतौर पर दूध के लिए पाली जाती हैं। वहीं पांच खास नस्ल के बकरों को देश ही नहीं विदेशों में, खासतौर पर खाड़ी देशों में बहुत पसंद किया जाता है। इसमे से ब्लैक बंगाल (पश्चिम बंगाल), बीटल (पंजाब) और बरबरा (यूपी) नस्ल का बकरा मीट के लिए बेहद पसंद किया जाता है।

एक्सपर्ट बताते हैं कि ये तीनों ही वो नस्ल हैं जिसके बकरे छरहरे और ठोस होते हैं। इनके अंदर चर्बी (वसा) की मात्रा कम होती है। इसके अलावा जमनापरी (यूपी) और जखराना (अलवर) नस्ल के बकरों को भी मीट के लिए बहुत पसंद किया जाता है। हमारे देश में ब्लैक बंगाल नस्ल के बकरे 3.75 करोड़, जखराना के 6.5 लाख, बीटल के 12 लाख और बरबरी के 47 लाख हैं। इसी तरह जमनापरी नस्ल के बकरे-बकरियों की संख्या 25.50 लाख है।

क्यों कम हुआ ऊन उत्पादन

देश में भेड़ के मीट का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। मीट उत्पादन के चलते ही दो राज्यों में ऊन का उत्पादन जीरो हो गया है। मीट के लिए काटी जा रहीं भेड़ों की संख्या साल 2021-22 के मुकाबले 2022-23 में 42 लाख ज्यादा थी। भेड़ के मीट की मांग एक्सपोर्ट से ज्यादा घरेलू बाजार में बढ़ रही है। यही वजह है कि ऊन का ज्यादा उत्पादन करने वाली नस्ल की भेड़ की संख्या कम होती जा रही है। मीट के लिए ज्यादा वजन वाली नस्ल की भेड़ें पाली जा रही हैं।

भारत में पाई जाने वाली भेड़ों की नस्ल

भारत के अलग-अलग राज्यों में भेड़ों की नेल्लोर, बेल्लोरी, मारवाड़ी, दक्कनी, कंगूरी, मरछेरी, पत्तनवाड़ी, हसन, जैसलमेरी, गद्दी, रामनद व्हाइट, चोकाला, छोटा नागपुरी, मद्रास रेड, नाली, मंडया, मालापुरा, बक्करवाल, पुगल और मागरा भेड़ों की खास नस्ल हैं। देश में भेड़ की 42 नस्लें पाली जाती हैं। देश में मौजूद सात करोड़ भेड़ों में से 35 फीसदी भेड़ तो सिर्फ पांच नस्ल की ही हैं।

किसान पशुओं के लिए उन्नत किस्मों की करें बोवनी

चरी के लिए सबसे बेस्ट ज्वार की खेती

भोपाल। जागत गांव हमार

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां पर 75 फीसदी से अधिक आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है, जो गांवों में निवास करती है। ये आबादी पेशे से किसान है, जो खेती-किसानी करने के साथ-साथ पशुपालन भी करती है। ये किसान दूध बेचकर अच्छी कमाई करते हैं। लेकिन कई बार उन्हें पशुपालन भी नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि पौष्टिक चारे के अभाव में भैंस और गायें दूध देना कम कर देती हैं। ऐसे में किसानों को अपने पशुओं को हरा चरा जरूर खिलाना चाहिए। इससे गाय- भैंस ज्यादा दूध देनी लगती हैं। पशु चिकित्सकों की मानें तो आप जितना अधिक दुधारू पशुओं को हरा चरा खिलाएंगे, वे उतना अधिक दूध देंगी। क्योंकि हरे चरे में बहुत सारे पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं, जिससे उनकी दूध देने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आप किसान हैं और साथ में पशुपालन भी करते हैं, तो आपको अपने पशुओं को ज्वार की हरी-हरी घास खिलाना चाहिए। इससे मवेशी पहले के मुकाबले ज्यादा दूध देने लगते हैं। खास बात यह है कि अभी ज्वार की बोवनी का समय भी चल रहा है। इसलिए किसान अपने खेतों में ज्वार की खेती शुरू कर सकते हैं।

ज्वार की बेहतरीन किस्में

दरअसल, ज्वार, खरीफ के मौसम में चारे की मुख्य फसल है। हालांकि, ज्वार की देसी किस्मों में प्रोटीन मात्रा कम होती है। इसकी उन्नत किस्मों में 7-9 प्रतिशत प्रोटीन होती है। यह दुधारू गाय-भैंस के लिए अच्छा चारा माना गया है। ऐसे पीसी 6, पीसी 9, यूपी चरी 1, यूपी चरी 2, पन्त चरी-3, एचसी 308, हरियाली चरी-1711 और कानपुरी सफेद मीठी ज्वार की उन्नत किस्में हैं। अगर किसान चाहें, तो इन किस्मों की बुवाई कर सकते हैं। ज्वार की इन किस्मों को चारे के रूप में खिलाने से मवेशियों की दूध देने की क्षमता बढ़ जाएगी।

इस वजह से बढ़ जाती है उपज

ऐसे ज्वार की बोवनी का सही समय जून-जुलाई का महीना माना गया है। अगर आपके इलाके में वर्षा नहीं हो रही है, तो पलेवा करके बुआई करें। छोटे बीजों वाली किस्मों के बीज 25 से 30 किलोग्राम और दूसरी किस्मों के बीज 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुवाई करनी चाहिए। अगर आप चाहें, तो लोबिया के साथ भी 2:1 के अनुपात में बो सकते हैं। इससे हरे चारे की पौष्टिकता व उत्पादकता बढ़ जाती है।

60 से 70 दिनों में तैयार हो जाएगी फसल

खास बात यह है कि ज्वार की बोवनी छिड़काव या सीडड्रिल विधि से ही करें। वहीं, उर्वरक का प्रयोग मृदा परीक्षणों के आधार पर करना चाहिए। सामान्यतौर पर 80-100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फॉस्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डाल सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन की दो तिहाई मात्रा तथा फॉस्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय खेत में डालना चाहिए। शेष एक-तिहाई नाइट्रोजन की मात्रा के 30-35 दिनों के बाद डालें। इससे 60 से 70 दिन में चारा काटने लायक हो जाएगा।

पुलिस ने सागर में किया बरामद

मप्र के पशुपालन मंत्री के गांव से 58 बकरियां चोरी

दमोह। जागत गांव हमार

दमोह जिले के पथरिया विधायक और प्रदेश सरकार के पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल के गृह गांव मड़ला से अज्ञात बदमाश बकरियां चुरा ले गए। पथरिया विधानसभा के नोरु मारा और राजलवारी गांव से भी बकरियां चोरी हुई थी। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस ने सागर जिले के बनडा में एक आरोपी को गिरफ्तार कर 58 बकरियां बरामद की। सभी बकरियों को देहात थाना लाया गया। पीड़ितों को बुला-बुलाकर बकरियां उनके सुपुर्द की गईं। देहात थाना के खिरिया मड़ला गांव निवासी सुरेंद्र बंसल ने बताया कि उसकी 10 बकरियां अज्ञात चोर चुरा ले गए थे। खोजबीन के बाद बकरियां नहीं मिली तो उसने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। मंत्री पटेल से भी बकरियों दिलाने निवेदन किया। इसके साथ ही धर्मपुरा क्षेत्र से भी कुछ बकरियां चोरी हुई थी। साथ ही पथरिया विधानसभा के राजलवारी गांव निवासी नत्थू आदिवासी को अज्ञात बदमाश बंधक बनाकर गांव के बाहर ले गए थे। हाथ-पैर बांधकर एक मेड पर डाल गए थे। उसकी 21 बकरियां चुराकर अपने साथ ले गए थे। परिजन बृजरानी आदिवासी ने बताया कि कुछ दिन पहले अज्ञात चोर गांव में घुसे थे। नत्थू को घर से उठाकर काफी दूर ले गए थे। हाथ-पैर बांधकर डाल गए थे। उसकी 21 बकरियां चुरा ले गए थे। इसी तरह नोरु मारा गांव निवासी नूरजहां ने बताया कि उसकी भी पांच बकरियां चोरी हुई थी। इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। देहात थाना के एसआई संजू सैया ने बताया कि देहात थाना के मड़ला गांव, धर्मपुरा और पथरिया थाना के नोरु मारा और राजलवारी गांव से एक बकरी चोर गिरोह बकरियां चुराकर ले गया था। इस बात की जानकारी एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी को दी गई। उनके निर्देशन में एक टीम गठित की गई। मुखबिर से सूचना मिली कि सागर जिले के बनडा में एक गिरोह के पास कुछ बकरियां बंधी हुई है। जब पुलिस ने मौके पर जाकर दबिश दी तो कुछ आरोपी भाग निकले और एक आरोपी पकड़ा गया जिससे 58 बकरियां बरामद कर देहात थाने लाया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया और सभी पीड़ितों को देहात आने बुलाकर उनकी बकरियां चिह्नित कराई गई। पीड़ितों ने अपनी बकरियों को पहचान लिया और उसके बाद बकरियां लेकर घर रवाना हो गए।

बाजार में हिल्सा मछली 1200 से 2000 रुपए किलो

नदी की तुलना में तेज विकास कराने में मिली सफलता

अब तालाब में हिल्सा फिश पालन हुआ आसान

भोपाल। जागत गांव हमार

आमतौर पर नदियों में मीठे जल में बढ़ने वाली हिल्सा मछली को तालाबों में पालने और उनका तेज विकास कराने में वैज्ञानिकों को सफलता मिली है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रोजेक्ट के तहत हिल्सा मछली को तालाब में पालकर 689 ग्राम वजन हासिल किया गया है। इसके साथ ही यह पता चला है कि सही प्रबंधन से नदियों की तुलना में तालाब में भी हिल्सा मछली का विकास किया जा सकता है। बता दें कि भारत में यह मछली कुछ नदियों के पानी में ही होती है, जिसकी वजह से इसकी बाजार में कीमत 1200 रुपए से लेकर 2000 रुपए किलो तक होती है। आईसीएआर सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे अधिक पसंद की जाने वाली बेशकीमती मछली हिल्सा (तेनुआलोसा इलिशा) ने लंबे समय से हमेशा शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है, जिसके कारण हाल ही में केंद्र सरकार ने कई रिसर्च प्रोजेक्ट के जरिए मछली को जलीय कृषि में लाने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में आईसीएआर-एनएएसएफ प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के तहत हिल्सा मछली के पालन के लिए शोध किया गया है।

अब तक का सर्वाधिक 689 ग्राम वजन पाया गया

आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार निगरानी के दौरान कोलाघाट में 689 ग्राम वजन (43.6 सेमी) की एक हिल्सा मछली दर्ज की गई। मछली की यह ग्रोथ 3 साल के पालन के दौरान देखी गई है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि हिल्सा मछली का यह आकार और वजन अब तक किए गए प्रयासों में सबसे बढ़िया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालाब में पाली गई हिल्सा का विकास खुले पानी की तुलना में बेहतर है, जिससे पता चलता है कि हिल्सा की जलीय कृषि की संभावना यानी यानी एक्वाकल्चर के लिए सही है।

आईसीएआर के प्रोजेक्ट में कई जगह हिल्सा पालन

आईसीएआर-एनएएसएफ प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में हिल्सा ब्रूडस्टॉक ग्रोथ प्रमुख उद्देश्य था। इसके लिए हिल्सा के बीज को विभिन्न स्थानों पर तालाबों में पाला गया। इनमें राहरा में मीठे पानी का क्षेत्र (केंद्रीय मीठा पानी जलीय कृषि संस्थान), काकद्वीप में खारा जल क्षेत्र (केंद्रीय खारा जल जल कृषि संस्थान) और मध्यवर्ती क्षेत्र कोलाघाट के जामित्या गांव में, मिदनापुर पूर्व, पश्चिम बंगाल (केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान में हिल्सा का पालन किया गया। ब्रूडस्टॉक तालाबों को कोलाघाट में गंगा नदी की सहायक नदी रूपनारायण से पानी दिया जाता है। वहां सभी दो तालाब सुविधाओं में अच्छी बढ़ोत्तरी और मछलियों का विकास दर्ज किया गया।

मछलियों को खास व्यवस्था में रखा गया

रिपोर्ट में बताया गया है कि मछलियों को विशेष रूप से तैयार किए गए भोजन के अलावा जीवित जूप्लांकटन का उनका पसंदीदा भोजन खिलाया गया। पानी की क्वालिटी लगभग 0.4-0.5 पीपीटी का खारापन और लगभग 800-1000 सेमी मीठे पानी की रखी गई है। पानी की क्षारीय स्थिति पीएच 7.4-7.5 रही और इसमें उचित ऑक्सीजन दर 7.4-7.5 मिलीग्राम प्रति लीटर रखी गई। आईसीएआर सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर की यह सफलता की कहानी एक सफल कैप्टिव हिल्सा कल्चर की संभावनाओं को साबित करती है अगर तालाबों का उचित प्रबंधन किया जाए।

देश में बासमती 200 वर्षों से अधिक समय से उगाई जा रही

भारत को बासमती जीआई टैग मिलने का रास्ता हुआ आसान

भोपाल। जागत गांव हमार

सुगंधित बासमती चावल के लिए जीआई टैग भारत को मिलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। बता दें कि पाकिस्तान ने भी बासमती चावल पर जीआई टैग हासिल करने के लिए आवेदन किया था, जिसे यूरोपियन यूनियन ने रद्द करते हुए दोबारा से पब्लिश किया है। एक्सपर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान के आवेदन का दोबारा प्रकाशन यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि जीआई टैग पाने के लिए भारत का रास्ता पहले से और साफ हो गया है। जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट के ओरिजिन को दर्शाता है। इसमें उसकी क्वालिटी, खूबी आदि का जिक्र होता है और इससे उस प्रोडक्ट की वैल्यू में इजाफा होता है। बासमती चावल के लिए जीआई टैग हासिल करने की लड़ाई भारत-पाकिस्तान के बीच चल रही है। पाकिस्तान ने कई पूसा से विकसित चावल की कई किस्मों की चोरी कर उत्पादन किया है। भारत ने 2018 में बासमती चावल पर जीआई टैग के लिए आवेदन किया था और पाकिस्तान ने भी जीआई टैग के लिए यूरोपीय यूनियन में आवेदन कर रखा है। यूरोपीय यूनियन ने नए नियमों के तहत सुगंधित चावल के लिए पाकिस्तान के जीआई टैग आवेदन को दोबारा प्रकाशित किया है। यूनियन ने अनुच्छेद 49 (5) के तहत 30 अप्रैल को जीआई एप्लिकेशन टैग को फिर से पब्लिश किया। जबकि, यूरोपीय यूनियन रेगुलेशन के अनुच्छेद 50 (2) के तहत पाकिस्तान के 23 फरवरी के आवेदन को रद्द कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट का कहना है कि इससे यह समझना और स्पष्ट हो गया है कि भारत को जीआई टैग मिल सकता है। ट्रेड एनालिस्ट एस चंद्रशेखरन ने कहा कि जीआई टैग के लिए पाकिस्तान के आवेदन का फिर से प्रकाशन स्पष्ट संकेत है कि भारत बासमती चावल का मालिक है।ऐसा इसलिए है क्योंकि जीआई टैग के लिए जुलाई 2018 में दायर भारत के आवेदन को यूरोपीय संघ विनियमन के अनुच्छेद 50 (2) के तहत लिस्ट किया गया है। जबकि, पाकिस्तान के आवेदन को दोबारा ईयू ने अपनी तरफ से पब्लिश किया है।

जीआई टैग मानक पूरा करता है भारत

भारत को जीआई टैग मिलने का रास्ता और आसान होने की अगली वजह यह है कि भारत में बासमती चावल 200 वर्षों से अधिक समय से उगाया जा रहा है। जबकि, पाकिस्तान ऐसा दावा नहीं कर सकता है। किसी उत्पाद के लिए संरक्षित जीआई टैग तभी दिया जाता है जब इस बात का सबूत पेश किया जाए कि उसे 200 से अधिक वर्षों से उगाया या प्रोड्यूस किया जा रहा है

पाकिस्तान ने माना भारत में उगाया जा रहा बासमती

अनुच्छेद 50(2) के तहत जीआई टैग के लिए आवेदन सीधे या किसी तीसरे देश के जरिए किया जा सकता है। हालांकि, पाकिस्तान के मामले में यूरोपीय यूनियन ने अनुच्छेद 49(5) लागू किया है, जिसमें कहा गया है कि जिस उत्पाद के लिए जीआई टैग मांगा गया है, उसे उसके मूल देश में संरक्षित किया जाना चाहिए। भारतीय और पाकिस्तानी आवेदनों के बीच अंतर यह है कि यूरोपीय यूनियन की ओर से जीआई टैग के लिए भारत के आवेदन के प्रकाशन में उल्लेख नहीं किया गया कि बासमती पाकिस्तान में उगाया जाता है। दूसरी ओर पाकिस्तान के आवेदन में कहा गया है कि यह चावल भारत के खास क्षेत्रों में भी उगाया जा रहा है। यूनियन ने इसको आवेदन में शामिल किया है। इसका मतलब है कि भारतीय आवेदन को प्राथमिक माना जा रहा है और यह बासमती चावल के जीआई टैग का आधार होगा।

देश में डेयरी सेक्टर को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा

आर्टिफिशल इंसेमीनेशन के नियमों की अनदेखी अब पड़ रही भारी

पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग की परेशानी आ रही सामने

भोपाल। जागत गांव हमार

गाय-भैंस वक्त से गर्मी में आकर गाभिन हो जाए, तय वक्त पर हेल्दी बच्चा देकर दूध देने लगे। अगर छोटे-बड़े किसी भी तरह के पशुपालक की बात करें तो उसका एक यही सपना होता है। एनिमल एक्सपर्ट की मानें तो पूरा डेयरी सेक्टर भी इसी पर टिका हुआ है। डेयरी में नुकसान और फायदे का रास्ता भी यही है। लेकिन एनिमल एक्सपर्ट का कहना है कि रिपीट ब्रीडिंग की परेशानी के चलते डेयरी सेक्टर को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। आर्टिफिशल इंसेमीनेशन (एआई) के नियमों की अनदेखी के चलते भी ये परेशानी बढ़ रही है। साथ ही सीमेन का चुनाव करते वक्त बुल की नस्ल और उसके इतिहास पर भी गौर नहीं किया जाता है। इसी परेशानी पर चर्चा करने के लिए हाल ही में गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, लुधियाना में हुए एक कार्यक्रम के दौरान भी डेयरी में होने वाले नुकसान के लिए रिपीट ब्रीडिंग को बड़ी वजह माना गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि पशु को गाभिन कराने में एआई की टाइमिंग का बड़ा महत्वम है। पानी का तापमान, कंटेनर का आकार और स्टेरेलाईज एआई गन प्रजनन क्षमता में अहम रोल निभाते हैं।

रिपीट ब्रीडिंग के कारण

रिपीट ब्रीडिंग को आम तौर पर एक ऐसी भैंस के साथ जोड़कर देखा जाता जिसे तीन बार गाभिन कराया गया और वो उसके बाद भी गर्भधारण नहीं कर सकती। एक्सपर्ट के मुताबिक इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी-कभी बहुत सारे कारणों में से सिर्फ एक-दो ही वजह बनते हैं। इस खबर में हम आपको ऐसे ही कई कारणों के बारे में बताएंगे।

निषेचन विफलता

एनोव्यूलेशन और विलंबित ओव्यूलेशन, ट्यूबल रुकावट, प्रीमैच्योर या शुरुआत में ही भ्रूण की मौत, ऑक्सीटोसिन की कमी, ऊर्जा की कमी, प्रोजेस्टेरोन की कमी, अतिरिक्त एस्ट्रोजन, खराब प्रजनन और प्रबंधन तकनीक और आनुवंशिक, पोषण संबंधी और संक्रमण।

दुधारू पशु में ज्यादा समस्या

एनिमल और डेयरी एक्सपर्ट के मुताबिक अधिक उम्र वाले और अधिक दूध देने वाले डेयरी पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग की घटनाएं ज्यादा सामने आती हैं। दूध उत्पादन का तनाव गोनैडोट्रॉफिन के विकास और रिलीज में बाधा डालता है, जिससे बार-बार प्रजनन होता है। बार-बार प्रजनन के लिए बैक्टीरिया की विभिन्न प्रजातियां भी जिम्मेदार होती हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टैफिलोकोकस, बैसिली, कॉर्नीबैक्टीरियम, ई. कोली, प्रोटियस।

सामान्य से अधिक मानसूनी वर्षा के संकेत, अच्छे उत्पादन की उम्मीद

डा. सत्येंद्र पाल सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र लहार (भिंड) मप्र

भारत में कृषि मानसून पर आधारित रही है। जब मानसून अच्छा रहता उस समय खरीफका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। यही नहीं मानसूनी वर्षा अच्छी होने पर रवी की फसलों पर भी प्रभाव पड़ता है, फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। यहां मानसूनी वर्षा की शुरुआत दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत मौसम विभाग की माने तो इस साल भारत समेत दक्षिण एशिया में मानसून सीजन यानी जून से सितंबर के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान है।

सामान्य तौर पर भारत में केरल से 2 जून से मानसून की शुरुआत हो जाती है जोकि पूरे देश में 30 सितंबर तक रहती है। इस बार अच्छी मानसूनी बरसात को देखते हुए किसान धान जैसी ज्यादा पानी चाहने वाली फसलें उगा सकते हैं।

साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम (एसएएससीओएफ) ने 2024 के मानसून के लिए जारी पूर्वानुमान में यह बात कही है। एसएएससीओफने में कहा है कि दक्षिण एशिया के उत्तरी, पूर्वी और हिस्सों के कुछ क्षेत्रों में सामान से कम वर्षा हो सकती है। इस दौरान अधिकतर क्षेत्रों में सामान्य से ऊपर तापमान रह सकता है। यह क्षेत्रीय जलवायु पूर्वानुमान दक्षिण एशिया के सभी नौ राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं (एनएमएचएस) ने तैयार किया है। इसमें एसएएससीओए के अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद ली गई है। फोरम ने कहा है कि वतज़मान में भारत में मध्यम अल नीनो की स्थितियां बनी हुई हैं। चार महीने के मानसून सीजन के पहले दो महीने यानी जून-जुलाई के दौरान अल नीनो की स्थिति तटस्थ बने रहने की उम्मीद है। उसके बाद के दो महीने यानी अगस्त-सितंबर के दौरान ला नीना की अनुकूल स्थिति बनने की पूरी संभावना है।

एलएएससीओएफकी रिपोर्ट आने से पहले ही भारत मौसम विज्ञान (आईएमडी) ने भारत में पहले ही सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान जता चुका है। पिछले महीने आईएमडी ने दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के लिए जारी अपने पूर्वानुमान में कहा था कि भारत में दीर्घकालिक औसत (एलपीए) का 106 फीसदी बारिश होगी। आईएमडी का कहना है कि चार महीने के मानसून सीजन के बाद के दो महीने अगस्त-सितंबर में अधिक वर्षा होगी, क्योंकि तब ला नीना की अनुकूल परिस्थितियां बनेगी। इस बार भारत मैं मानसून के सामान्य रहने के साथ अच्छी वर्षा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा भी भारत में 106प्रतिशत तक वर्षा होने की घोषणा की गई है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस बार अल नीनो की जगह पर ला नीना का प्रभाव देखा जा रहा है। यह अल नीनो और ला नीना कैसे उत्पन्न होता है और यह क्या है इसके बारे में समझने की जरूरत है। लेकिन भारत के आम जनमानस व किसान अल नीनो व ला नीना के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। जिसे समझने की जरूरत है। सामान्य तौर पर अल नीनो दक्षिणी हवाओं से पैदा हुआ मौसम का एक चक्र है जिससे कि विश्व के पूरे मौसम के तापमान पर असर पड़ता है। अल नीनो समुद्री सतह में औसतन से ज्यादा गर्मी होने के कारण 4 से 5 साल के बाद विकसित होता रहता है। समुद्री सतह के गर्म होने के कारण गर्मी पैदा होती है और जो हवाएं चलती हैं उन हवाओं

में और ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है। इस कारण वर्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। फलस्वरुप कई इलाकों में कम वर्षा और सूखा की स्थिति पैदा होती है।

समुद्री सतह का तापमान जब कम अथवा ठंडा होता है तब ला नीना की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके कारण समुद्री सतह पर ठंडी और नम हवाएं चलती हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादा वर्षा की संभावना रहती है। इस प्रकार से हम साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि अल नीनो समुद्री सतह के गर्म होने तथा गर्म हवाओं से संबंधित है। वहीं दूसरी तरफ ला नीना समुद्री सतह के ठंडे और नम हवाओं से संबंधित है।पिछले तीन साल से भारत अल नीनो के फेज में चल रहा था। गर्मी ज्यादा बढ़ रही थी और मानसून के पैटर्न में गर्मी के कारण ज्यादा भाप बनती थी। इसके चलते एक स्थान पर ज्यादा बारिश हो जाती थी तथा लंबे अंतराल तक फिर सूखा रहता था। हम कह सकते हैं कि पूरे देश में एक प्रकार से समान (यूनिफॉर्म) रूप से वषाज़ नहीं हो रही थी। इस वर्ष भारत ला लीना के फेज में जा रहा है। इसके चलते अगस्त-सितंबर में ला नीना प्रभाव सक्रिय रूप से ज्यादा रहेगा। मानसून समय से आएगा तथा सामान्य वर्षा होगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान स्पष्ट रूप से इस बात के भी संकेत दे रहे हैं कि इस बार ज्यादातर क्षेत्रों में एक समान वर्षा होगी। वहीं अगस्त-सितंबर में बहुत अच्छी वषाज़ होने के संकेत हैं।

इस समय में मई माह में भी बहुत तीव्र गर्मी पड़ रही है। उत्तर भारत के कई राज्यों एवं शहरों में तापमान 47 और 48 डिग्री तक जा रहा है। मई-जून में अच्छी गर्मी इस बात का संकेत देती है कि मानसून तय समय पर आकर अच्छी बरसात की शुरुआत करेगा। किसानों को भी पिछले कुछ सालों की तुलना में इस वर्ष अच्छी वर्षा की भविष्यवाणी के चलते खरीफमौसम में फसलों से अच्छा उत्पादन मिलने की उम्मीद जगी है। अब देखना यह होगा कि मानसून तय समय पर आकर पूरे बरसाती सीजन में लगातार समय-समय पर समान रूप से बरसता रहे। हालांकि पिछले एक दशक में देखने को मिल रहा है कि मानसूनी बरसात में बहुत अधिक असमानता देखी जा रही है। जिसके चलते बरसात के दिन घटने, कुछ ही दिन में पूरे माह की बरसात हो जाने इसके बाद काफी लंबे समय तक बरसात नहीं होने तथा एक समान रूप से काफी लंबे क्षेत्र में एक साथ बरसात नहीं होने की स्थिति देखी गई है। यह सभी स्थितियां वर्षा जल संचय तथा खरीफ मौसम की फसलों के हिसाब से अच्छी नहीं मानी जा सकती हैं।

मानसूनी सीजन में यदि समय-समय पर आवश्यकता अनुसार पानी बरसता रहे, ज्यादा लंबा ड्राईस्पेल न हो और बहुत अधिक एक साथ ना हो, ऐसी स्थितियां बहुत अच्छी मानी जाती हैं। आशा करते हैं कि इस साल किसानों के लिए ऐसी परिस्थितियों बनेगी और पूरे खरीफ सीजन में समय-समय पर अच्छी बरसात होगी। जिसका सीधा लाभ खरीफ फसलों के साथ ही आगामी रवी फसलों को भी मिल सकेगा। इतना ही नहीं अच्छी मानसूनी बरसात का सबसे अधिक लाभ जमीन की भूगर्भ जल धारण क्षमता को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। इसलिए किसानों को चाहिए कि वह गर्मियों के इस मौसम में खेतों की गहरी जुताई तथा मेड़बंदी पर विशेष ध्यान दें। जिससे जल को अधिक से अधिक अपने खेतों के अंदरसंचित किया जा सके।

महिलाओं की बकरी पालन प्रबंधन में भागीदारी

» डॉ. व्ही एन गौतम
» डा. आकांक्षा पांडेय
» डॉ. दुष्यंत कौशिक
सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय अवं अनुसन्धान केंद्र कोरबा

हमारे देश में ग्रामीण महिलायेएं कृषि, पशु पालन एवं संबंधित क्षेत्रों में मुख्य भूमिका निभाती हैं। महिलायें बकरी पालन में इसका भरण पोषण, प्रजनन, स्वास्थ्य संबंधी प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। वैसे बकरियों के रख रखाव में अधिक परेशानी नहीं आती है। महिलाओं का गरीबी उन्मूलन एवं पारिवारिक पोषण जैसे कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं गरीबी उन्मूलन प्रयासों की सफलता का केन्द्रबिंदु है तथा निर्धनतम परिवार मुख्यत: महिलाओं की आर्थिक उत्पादकता पर निर्भर रहता है। महिलाएं परिवार को गरीबी से बाहर निकालने के लिये ठोस एवं सक्रिय भूमिका निभाती हैं चूंकि बकरी ऐसा पशुधन जिससे साल भर आमदनी मिलती रहती है।

बकरी पालन के लिए व्यवस्थित फार्म के लिये भूमि का चुनाव मुख्य मुद्दा है। भूमि ऐसी जगह पर होनी चाहिये जो कि मुख्य मार्ग से नजदीक या जुड़ा हो जिससे की आवागमन में सुविधा मिले। फार्म के नजदीक बंजर भूमि जहां बकरियां चर सकें तथा जंगल के आस पास हो। यहां पर सूखी पत्तियां तथा हरे भरे झाडियों से पेट भर सकते हैं। फार्म के चारों ओर पेड़ लगा देना चाहिये, इससे कई फायदे होते हैं, जैसे हरा चारा के साथ गर्मी के दिनों में छाया प्रदान करेगा।

नस्ल का चयन: नस्ल का चुनाव जगह की आवश्यकतानुसार किया जाता है। बकरी से दूध मांस, रेशे आदि प्राप्त होते हैं, इसलिये इन बातों को ध्यान में रख कर बकरी फार्म स्थापित करना चाहिये। उदाहरण स्वरूप यदि मांस उत्पादन हेतु अपनायी गयी हो तो ऐसे नस्ल का चुनाव करना होगा, जिससे अधिक प्रजनन की क्षमता हो, दाने को मांस में परिवर्तित करने की प्रवृति तथा बढोत्तरी दर में वृद्धि हो। इससे सुनिश्चित समय में अधिक मांस का उत्पादन हो सकेगा।

बकरियों की उपलब्धता: बकरी पालन सुचारु रूप से चलाने हेतु अच्छे नस्ल की बकरियां खरीदनी चाहिये। इसके लिये यह जानना जरूरी हो जाता है कि प्रमुख नस्ल की बकरी का निवास स्थान देश के किस भाग में स्थित है अथवा कोई सरकारी फार्म या कोई व्यवस्थित फार्म हो तो वहीं से खरीदना उचित रहेगा। प्रत्येक नस्ल की बकरी की कोई विषेषताएं होती है, अत: बाह्य गुण देखकर पहचाना जा सकता है। नर का चुनाव करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरुरी होता है-शारीरिक बनावट, नस्ल, गुणवत्ता इत्यादि।

आवास व्यवस्था: बकरियां सामान्यत: पहाड़ी क्षेत्र की उत्पति है तथा वह बंधना पसंद नहीं करती। इन्हें साफहवा तथा साफऔर स्वच्छ जगह पसंद आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बकरियों के लिये विशेष घर की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु इन्हें मौसम के विपरित प्रभाव तथा जंगली पशुओं से बचाव के लिए घर की आवश्यकता होती है। जहां पर अधिक संख्या में बकरी रखना हो वहां

पर हवादार आवास होना जरुरी है। स्थाई कमरे का निर्माण ईंट, सीमेंट व कंकड का प्रयोग करके इस प्रकार बनाया जाना चाहिये, जिससे कि मौसम की अधिक गर्मी अथवा ठंड से पशु सुरक्षित रह सके। एक कमरे में 8 से 10 बकरियां रख सकते हैं। बकरा रखने का कमरा अलग बनाना चाहिये। बकरी फार्म के आसपास पेड़ लगाना अच्छा रहता है जो कि विपरित वातावरण में सुरक्षा प्रदान करता है। बाड़े को चारो ओर से जालीदार तार से घेर देना चाहिये, इसी जगह पर पानी पीने की व्यवस्था भी हो। बकरी को दिन में दो बार और यदि हो सके तो अधिक बार पानी पिलाना खासकर गमीज़ के दिनों में जरुरत पडती है। मेमनों के लिये अलग से बाड़ा होना चाहिये।

आजकल अक्सर छत बनाने में एस्बेस्टस सीमेंट की चादरों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे गर्मी तथा ठंडक से बचाव होता है। यदि अधिक सर्दी या गर्मी पडे तो चददरों के ऊपर घास या पूआल बिछा सकते हैं। रात के समय बकरी को सूखी एवं ढकी हुई जगह सोने के लिये चाहिये। बकरी को ढकी हुई जगह मिले तो उसे ज्यादा से ज्यादा शक्ति अपने आप को गर्म रखने की बजाय अधिक दूध पैदा करने में लगाने का मौका मिलता है । कमरा जिसकी लम्बाई 5 फीट 2.5 - 3 फीट चैडी हो तो उसमें दो बकरियां रख सकते हैं। मां और बच्चे को ऐसी जगह बांधना चाहिये कि मां बच्चे को देख सके। बकरियों का आवास दलदली जमीन तालाब के किनारे नहीं होना चाहिये।

विभिन्न आयु वर्ग के बकरे - बकरियों को अलग अलग कमरे में रखना चाहिये। 3 माह के बाद नर तथा मादा बच्चों को अलग कमरे में रख सकते हैं। गाभिन, व्यात तथा बीमार बकरियों के लिए अलग कमरे होने चाहिये। बकरी घर की सफाई हर रोज होनी चाहिये। यदि जमीन में फर्शी हो तो सर्दियों में फर्श पर घास फूस अथवा पुआल आदि बिछाना चाहिये जिससे कि फर्श गरम रह सके। उपयोग किये गये घास फूस को प्रतिदिन धूप में सुखा लेना बकरे - बकरियों के लिए अच्छा रहता है। गांव में जिसके पास बकरियों की संख्या कम रहती है, रात के समय अपने सोने वाले कमरे या बगल में रखते हैं जिससे की जंगली जानवर से बचाया जा सके या बकरी आवास की चार दीवारी या सीमा चारों ओर से कांटे से घिरी होना चाहिये।

कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि दर 50 हजार सालों की तुलना में 10 गुना तेज

शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने प्राचीन अंटार्कटिका की बर्फ का गहन रासायनिक विश्लेषण किया, जिससे पता चला कि आज वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि की दर पिछले 50 हजार सालों की तुलना में 10 गुना तेज है। नेशनल एकेडमी ऑफसाइंसेज में प्रकाशित नतीजे पृथ्वी के अतीत में अचानक जलवायु में हुए बदलाव की अवधि के बारे में अहम खुलासा करते हैं। साथ ही आज जलवायु में हो रहे बदलावों के संभावित प्रभावों की नई जानकारी को सामने लाते हैं। शोधकर्ताओं ने शोध में पिछले प्राकृतिक सीओ2 वृद्धि की अब तक की सबसे तेज दर का पता लगाया और बताया कि आज की यह वृद्धि दर, मुख्य रूप से मानवजनित उत्सर्जन के कारण इतनी ज्यादा है।

कार्बन डाइऑक्साइड (सिओ2) एक ग्रीनहाउस गैस है जो वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो यह ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण जलवायु को गर्म कर देती है। अतीत में, हिमयुग चक्रों और अन्य प्राकृतिक कारणों से सीओ2 के स्तर में उतार-चढ़ाव होता रहा है, लेकिन आज मानवजनित उत्सर्जन के कारण यह बढ़ रही है। शोध के मुताबिक, सैकड़ों-हजारों वर्षों में अंटार्कटिका में बनी बर्फ में हवा के बुलबुले में फंसी प्राचीन वायुमंडलीय गैसें शामिल हैं। पिछले शोध से पता चला है कि पिछले हिमयुग के दौरान, जो लगभग दस हजार साल पहले समाप्त हुआ था, ऐसे कई मौके थे जब कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर औसत से बहुत अधिक बढ़ गया था। लेकिन वे माप इतने विस्तृत नहीं थे कि तीव्र बदलावों की पूरी प्रकृति को उजागर कर सकें, जिससे वैज्ञानिकों की यह समझने की क्षमता सीमित हो गई। वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट डिवाइड आइस कोर के नमूनों का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि उस अवधि के दौरान क्या हो रहा था। उन्होंने एक पैटर्न की पहचान की, जिससे पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड में ये उछाल उत्तरी अटलांटिक में ठंड में कमी के साथ हुआ, जिसे हेनरिक इवेंट के रूप में जाना जाता है, जो दुनिया भर में अचानक जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। शोधकर्ता के मुताबिक, ये हेनरिक घटनाएं वास्तव में अहम हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे बड़ी प्राकृतिक वृद्धि 55 सालों में लगभग 14 भाग प्रति मिलियन की वृद्धि हुई। यह छलांग लगभग हर 7,000 वर्षों में एक बार हुई थी। आज की दरों पर, उस स्तर की वृद्धि में केवल पांच से छह साल लगते हैं। साक्ष्य बताते हैं कि प्राकृतिक कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के पिछले समय के दौरान, गहरे समुद्र के प्रसार में अहम भूमिका निभाने वाली पश्चिमी हवाएं भी मजबूत हो रही थीं, जिससे दक्षिणी महासागर से सीओ2 तेजी से निकल रही थी।

अन्य शोधों से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये पछुआ हवाएं अगली सदी में मजबूत होंगी। शोधकर्ताओं ने कहा कि नए निष्कर्षों से पता चलता है कि यदि ऐसा होता है, तो इससे मानवजनित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की दक्षिणी महासागर की क्षमता कम हो जाएगी।

शोधकर्ता ने शोध के हवाले से कहा, हमारे द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा लेने के लिए हम दक्षिणी महासागर पर निर्भर हैं, लेकिन तेजी से बढ़ती दक्षिणी हवाएं ऐसा करने की उसकी क्षमता को कमजोर करती हैं।

कृषि विज्ञान केंद्र पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन, 6 माह के कार्यक्रमों की रूपरेखा का प्रस्तुतीकरण

पुरानी प्रजातियों के बजाय नई प्रजातियों पर काम करने की जरूरत

कृषि तकनीकी को किसानों तक लेकर जाएं वैज्ञानिकः निदेशक

भिंड/लहार। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र पर खरीफ2024 की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विगत 6 माह की कार्य प्रगति तथा आगामी 6 माह के कार्यक्रमों की रूपरेखा का प्रस्तुतीकरण किया गया। बैठक में वैज्ञानिक, अधिकारी, एफपीओ, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के अलावा आईसीएआर के विभिन्न संस्थाओं के वैज्ञानिकों द्वारा भाग लेकर सुझाव प्रस्तुत किए गए।

सर्वप्रथम केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एसपी सिंह द्वारा केंद्र की विगत 6 माह अक्टूबर से माचज़ तक की कार्य प्रगति एवं आगामी अप्रैल से सितंबर तक के 6 माह मैं किये जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा का प्रस्तुतीकरण किया गया। डॉ. सिंह द्वारा पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से ऑनलाइन एवं ऑफ लाइन मोड में विस्तार से प्रस्तुति दी गई।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि बतौर बोलते हुए राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के निदेशक विस्तार सेवाएं डॉ. वाय.पी. सिंह ने कहा कि पुरानी प्रजातियों के बजाय नई प्रजातियों पर काम करने की जरूरत है।

किसानों के अनुरूप फार्मिंग सिस्टम पर कार्य किया जाए

उन्होंने कहा कि आज तकनीकी का दौर है इसलिए वैज्ञानिक नवीनतम तकनीकी को किसानों तक लेकर जाएं जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। सिंचित, असिंचित, छोटे किसान एवं बड़े किसानों के अनुरूप फार्मिक सिस्टम कृषि मॉडल पर कार्य किया जाए जिससे किसानों को ज्यादा लाभ मिल सके।

बेसल लाइवस्टॉक मिशन के तहत बकरी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा

चारा अनुसंधान केंद्र, झांसी के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. बीएस कुशवाहा द्वारा भिंड जिले में भदावरी भैंस को बढ़ावा दिए जाने और उससे होने वाले लाभ का प्रस्तुतीकरण किया गया। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, मथुरा के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. अनुपम कृष्ण दीक्षित ने भिंड जिले में बकरी पालन को बढ़ावा दिए जाने, बकरी नस्ल सुधार एवं एवं बकरी विपणन के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए गए। डॉ दीक्षित ने बताया के भारत सरकार द्वारा संचालित बेसल लाइवस्टॉक मिशन के तहत छोटे पशुओं खासकर बकरी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इस योजना में 100, 200, 300, 400, 500 बकरियों के प्रोजेक्ट लगाने पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. विकास कुमार यादव ने कहा कि किसानों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कृषि विषयों पर संस्थान एवं किसान प्रक्षेत्र पर प्रयोग किए विषयों पर किसानों द्वारा अपनाई गई तकनीकी को कंट्रोल मान कर नई तकनीकी का उत्पादन के साथ-साथ आर्थिक विश्लेषण किया जाय।

प्राकृतिक खेती पर जागरूक किया जाए

भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं जैसे प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ पर भी प्रयोग एवं जागरूकता कार्यक्रम किए जाएं। साथ ही गांव, पंचायत या ब्लॉक स्तर पर किसान समूह, सहकारी संस्था, एफपीओ आदि को मजबूत किया जाए, जिससे केविके द्वारा विकसित मॉडल के इनपुट और उत्पाद को प्रोसेस करने में और आसानी हो सके। बैठक में आईएआरआई, हजारीबाग, झारखंड से जुड़ी वैज्ञानिक डॉ. शिल्पी करकेटा, कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर के प्रभारी डॉ. एसएस कुशवाहा द्वारा अपने विचार और सुझाव रखे गए। बैठक में कृविके मुरैना, दतिया के वैज्ञानिक, केंद्र के डॉ करणवीर सिंह, डॉ आरपीएस तोमर, डॉ रूपेंद्र कुमार, डॉ एनएस भदौरिया, निशांत प्रभाकर, परमेश सोनी, दीपेंद्र शर्मा पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज शर्मा, एनआरएलएम के मनोज शिवहरे, स्वसहायता समूह की शिवा कुमारी, महिला बाल विकास से राधा राठौर, विनोद दुबे, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, एफपीओ से जुड़े कार्यकर्ता, प्रगतिशील किसान आदि द्वारा बैठक में भाग लिया।

कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी की 35 वीं वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की बैठक

समन्वित कृषि प्रणाली को बढ़ावा दें: वायपी सिंह

शिवपुरी। जागत गांव हमार

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर एवं भाकृअनुप-कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान क्षेत्र 9 जबलपुर के अधीन कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी की 35 वीं वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की बैठक कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवपुरी पर आयोजित हुई। वैज्ञानिक परामर्श समिति बैठक का उद्देश्य जिले के भौगोलिक एवं जलवायु दृष्टिकोण के अनुकूल कृषकों के लिए नई तकनीकों का समावेश प्रक्षेत्र प्रयोग परीक्षण, प्रदर्शन एवं प्रसार गतिविधियों के द्वारा जिले के लिए बनाई जाने वाली कार्ययोजना का जिले के संबंधित विभाग के विभाग प्रमुखों एवं वरिष्ठ कार्यालय के अधिकारियों के दिये निर्देशन में सुदृढ़ बनाना होता है। जिससे जिले में कृषकों के लिए अनुकूल कृषि एवं नवीन तकनीकियों का प्रसार हो सके। बैठक में विगत छः माह तक की प्रगति एवं आगामी 6 माह के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना की कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. पुनीत कुमार के निर्देशन में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एमके भार्गव द्वारा पॉवर पाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

टमाटर उत्पादन के लिए मूल्य संवर्धन की तकनीकियों को जोड़ें: एसआरके सिंह

बैठक की अध्यक्षता कर रहे डॉ. वाय. पी. सिंह, निदेशक विस्तार सेवाएं, राविसिंकृविवि ग्वालियर द्वारा कार्य प्रगति पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए आगामी योजना के लिए महत्वपूर्ण सुझावों में छोटे एवं सीमांत कृषकों के लिए निरंतर और सतत आय प्राप्ति के लिए वर्षा आधीन एवं सिंचित क्षेत्रों के लिए अलग-अलग समन्वित कृषि प्रणाली के मॉडलों एवं तकनीकियों से अवगत कराने के लिए सुझाव दिए जो वर्तमान जलवायु परिवेश एवं कम होते भू जल स्तर को बढ़ाने में भी लाभकारी होगा। मुख्य अतिथि डॉ. एसआरके सिंह, निदेशक भाकृअनुप-कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान क्षेत्र 9 जबलपुर ने भी कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी में विगत माह किए भ्रमण एवं जिले के परिप्रेक्ष्य में संभावित गतिविधियों के लिए सुझाव देते हुए शिवपुरी जिले में बहुतायत में होने वाले टमाटर उत्पादन के लिए मूल्य संवर्धन की तकनीकियों से जोड़ने के लिए सुझाव दिया। जिले के संबंधित विभागों के प्रमुखों की ओर से कार्ययोजना हेतु टमाटर नर्सरी प्रबंधन, समन्वय में कृषि तकनीकों का और अधिक प्रसार बढ़ाने के लिए सुझाव दिए।

परामर्शदात्री की बैठक में इनकी रही उपस्थिति

वैज्ञानिक परामर्शदात्री की बैठक में डॉ. किरण रावत, सहायक संचालक कृषि, इंजीनियर अंकित सेन सहायक कृषि यंत्री, डी. एस. सचान मत्स्य इंस्पेक्टर, दयाशंकर पाण्डे प्रभारी अधिकारी बीज निगम, इंदवीर सिंह उद्यान विभाग, रामगोपाल वर्मा, लोकेन्द्र सिंह बीज उत्पादक समिति के साथ-साथ प्रगतिशील कृषक अवधेश वर्मा, रामस्वरूप धाकड़ एवं राम गोपाल गुप्ता की सहभागिता रही। कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों जे.सी. गुप्ता, डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह, डॉ. ए.एल. बसेड़िया, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी योगेश चन्द्र रिखाड़ी, डॉ. एनके कुशवाहा, लेखाधिकारी सतेन्द्र गुप्ता एवं स्टेनो आरती बंसल की सहभागिता रही।

अटरिया में मनाया गया विश्व मधुमक्खी दिवस

मधुमक्खियों को संरक्षित करने की आवश्यकता

रीवा। जागत गांव हमार

कृषि महाविद्यालय रीवा मप्र. के अधिष्ठाता डॉ एस के त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं डॉ ए के पांडेय प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र रीवा के निर्देशन में विश्व मधुमक्खी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में पौध सरंक्षण वैज्ञानिक डॉ अखिलेश कुमार द्वारा ग्राम अटरिया, सेमरिया, रीवा में विश्व मधुमक्खी दिवस पर अपने उद्बोधन में कहा कि फसलों एवं फलों के साथ-साथ धरती पर पाए जाने वाले अन्य पौधों में परागण 80 से 85 प्रतिशत कीटों द्वारा होता है। जिसमें से 70 प्रतिशत परागण केवल मधुमक्खियों द्वारा होता है। इसलिए आज मधुमक्खियों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इनसे प्राप्त होने वाले सह उत्पाद मधु, रॉयल जेली, मोम, प्रोपोलीस, विष से मधुमक्खी पालक के लिए आय का अच्छा स्रोत भी है। फसलों, फलो व सब्जियों में देखा गया है कि औसत 15 प्रतिशत उत्पादन के साथ गुणवत्ता बढ़ जाती है।

कार्यक्रम में केंद्र के वैज्ञानिक डॉ संजय सिंह ने मधुमक्खी पालन के महत्व पर प्रकाश डाला और कृषकों को कीटनाशकों के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर गाँव के प्रगतिशील कृषकों के साथ-साथ सरपंच श्यामकली साकेत उपस्थित रही।

श्योपुर में किसानों से अब तक 56226.88 मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया

समर्थन मूल्य पर गेहू खरीदने में श्योपुर संभाग में पहले नंबर पर, मुरैना फिसड्डी

इतना गेहूं अब तक संभाग के अन्य किसी दूसरे जिले में खरीदा नहीं गया

श्योपुर। जागत गांव हमार

समर्थन मूल्य पर चल रही गेहूं खरीदी में श्योपुर जिला पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में अव्वल स्थान पर है। क्योंकि श्योपुर जिले में अभी तक 4 हजार 706 किसानों से 56 हजार 226.88 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है और इतनी खरीदी संभाग के किसी भी जिले में अभी तक नहीं की गई है। यही वजह है कि संभाग में श्योपुर टॉप पर है, जबकि गुना और मुरैना जिले फिसड्डी चल रहे हैं। हालांकि गुना जिले में 6419 मैट्रिक टन गेंहू खरीदा जा चुका है,लेकिन मुरैना जिले में अभी एक भी दाना गेहूं का समर्थन मूल्य पर खरीदा नहीं जा सका है।

यूं तो श्योपुर जिले में गेंहू खरीदी के लिए 32 खरीदी केन्द्र बनाए गए है, लेकिन अभी तक किसान 31 खरीदी केन्द्रों पर ही गेहूं बचने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि इस बार गेहूं खरीदी केन्द्रों पर किसानों की उतनी भीड़ नहीं उमड़ पाई है,जितनी भीड़ बीते वर्षो के दौरान गेहूं खरीदी केन्द्रों पर उमड़ी रही है। इसके पीछे कारण मंडी में गेहूं का अच्छा भाव रहा है। क्योंकि भाव अच्छा होने की वजह से ज्यादातर किसानों ने अपने गेहूं मंडी में जाकर ही बेच दिया है। भाव थोड़ा कम हुआ, तब खरीदी केंद्रों पर गेंहू बेचने के लिए किसानों की भीड़-भाड़ देखने को मिली। बताया गया है कि 17 मई की स्थिति में श्योपुर जिले में 4706 किसानों से 56226.88 मैट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। हालांकि यह खरीदी टारगेट के मुकाबले कम है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों में यह खरीदी सबसे ज्यादा है।

संभाग में दतिया दूसरे तो भिंड तीसरे स्थान पर

समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के मामले में श्योपुर जिला ग्वालियर चंबल संभाग में पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर दतिया और तीसरे स्थान भिंड जिला है। चौथे स्थान पर शिवपुरी और पांचवे नंबर पर ग्वालियर है। लेकिन मुरैना जिला सबसे ज्यादा फिसड्डी है,क्योंकि मुरैना जिले में 28 गेहूं खरीद केंद्र होने के बाद भी एक भी दाना गेहूं का खरीदा नहीं जा सका है।

टारगेट पूर्ति के लिए बढ़ाई खरीदी की तारीख, अब 31 तक होगी खरीदी

समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का टारगेट फिलहाल काफी दूर है,इसलिए शासन स्तर से इस टारगेट की पूर्ति करने के लिए गेहूं की खरीदी की तारीख बढ़ा दी गई है। पहले गेंहू खरीदी की अंतिम तारीख 20 मई निर्धारित थी,लेकिन अब यह तारीख बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। श्योपुर जिले को एक लाख मैट्रिक गेहूं खरीदी का टारगेट मिला है, जो काफी दूर लग रहा है।

जिले वार गेंहू खरीदी एक नजर में

जिला	केंद	गेहूं बेचने वाले किसान	खरीदी
श्योपुर	32	4706	56226.88
मुरैना	28	00	00
भिंड	31	2711	19529
ग्वालियर	43	1385	14798.94
शिवपुरी	41	2010	15788.48
गुना	24	744	6419.35
दतिया	49	4683	36153.94
अशोकनगर	25	970	8362.05

फसलों की बंपर आवक बढने से बदलने जा रही श्योपुर मंडी की ग्रेड

श्योपुर की कृषि उपज मंडी को फिर से मिलेगा ए ग्रेड का दर्जा

श्योपुर। जागत गांव हमार

जैदा स्थित श्योपुर की कृषि उपज मंडी इन दिनों फसलों की बंपर आवक से चमक गई। धान की बंपर आवक होने के बाद अब गेंहू की फसल की भी श्योपुर मंडी में बंपर आवक हुई है। भलेही सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीद केन्द्रों खोल दिए गए, लेकिन इसके बाद भी श्योपुर मंडी में इस बार गेंहू की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। धान और गेंहू की बंपर आवक से जहां श्योपुर मंडी की आय में इजाफा हुआ है। वहीं बी ग्रेड की मंडियों मे शामिल श्योपुर की कृषि उपज मंडी ने प्रदेश स्तर पर बेहतर स्थान हांसिल किया है। इसलिए मप्र के मंडी बोर्ड के द्वारा श्योपुर की कृषि उपज मंडी को फिर से ए ग्रेड का दर्जा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि मंडी बोर्ड के द्वारा इस तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिसके चलते उम्मीद की जा रही है लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद कभी भी श्योपुर मंडी को ए ग्रेड की मंडी का दर्जा मिल सकता है। ए ग्रेड का दर्जा मिलने पर श्योपुर कृषि उपज मंडी में न सिर्फ किसानों के लिए सुविधाएं बढेगी,बल्कि मंडी कर्मचारियों को भी फायदा होगा। यहां बता दें कि वर्ष 2015 तक श्योपुर मंडी ए ग्रेड की मंडियों में शामिल थी, लेकिन फसल आवक में कमी आने से मंडी की आय में भी कमी हो गई।

पिछले साल मिला बी ग्रेड की सर्वश्रेष्ठ मंडी का अवॉर्ड

वर्ष 2016 में ए ग्रेड से बी ग्रेड की मंडियों में शामिल हुई श्योपुर की कृषि उपज मंडी में आय की बढोत्तरी धान की खरीदी शुरू होने के बाद हुई है। दरअसल श्योपुर क्षेत्र में बडी तादात धान की फसल होने लगी है। मगर श्योपुर मंडी में धान की खरीदी न होने के कारण जिले के किसान धान की फसल बेचने के लिए राजस्थान की कोटा और बारां मंडियों में ले जाते थे। लेकिन वर्ष 2021 से श्योपुर मंडी में धान की खरीदी शुरू हो गई। तब से श्योपुर मंडी में धान की बंपर आवक होने लगी। धान के बाद गेंहू की बंपर आवक होने से मंडी की कुल फसल आवक का आंकडा 2 लाख टन से बढकर 3 लाख टन पहुंच गया। जिसके चलते वर्ष 2023 में श्योपुर मंडी को बी ग्रेड की मंडियों में सर्वश्रेष्ठ मंडी का अवार्ड मिला है। मंडी बोर्ड के द्वारा सर्वश्रेष्ठ मंडी का ये अवार्ड 4 अगस्त 2023 को श्योपुर मंडी सचिव एसडी गुप्ता को

मंडी में बढ़ेगी किसानों के लिए सुविधाएं

कृषि उपज मंडी श्योपुर को बी ग्रेड से ए ग्रेड की मंडियों में शामिल किए जाने पर में विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों के साथ किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। शासन स्तर से मंडी विकास के लिए अनुदान राशि में बढ़ोतरी होगी। जिससे मंडी में किसानों के लिए सुविधाएं बढाई जाएगी। वहीं स्टाफ की संख्या में भी इजाफा होगा। वर्तमान में श्योपुर मंडी में स्टाफ कम है।

मंडी में फसल की आवक और आय में बढोत्तरी हुई है। जिसके चलते श्योपुर मंडी को 4 अगस्त 2023 बी ग्रेड की मंडियों में सर्वश्रेष्ठ मंडी का पुरस्कार मिला है और अब ए ग्रेड का दर्जा भी मिलने की पूरी उम्मीद है।
एसडी गुप्ता, सचिव,कृषि उपज मंडी,श्योपुर

श्योपुर मंडी में तीन सालों में फसल की आवक और मंडी शुल्क

वर्ष	आवक (टन में)	मंडी शुल्क (रूपए में)
2021-22	298603	10 करोड 72 लाख 35 हजार 125
2022-23	259005	14 करोड 90 लाख 14 हजार 63
2023-24	308863	11 करोड 57 लाख 54 हजार 475

नोट-वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में मंडी शुल्क में कमी शासन स्तर से शुल्क दर घटाने के कारण आई है।

गाय-भैंस को खिलाएं हरी-हरी घास, पशुओं के चारे में नंबर वन है मकचरी

भोपाल। भारत में किसान बड़े स्तर पर पशुपालन करते हैं। देश में करोड़ों लोगों के घर का खर्च पशुपालन से चल रहा है। वहीं, लाखों लोग ऐसे भी हैं, जो दूध, दही, घी और मक्खन बेचकर महीने में अच्छी कमाई कर रहे हैं। लेकिन कभी-कभी इन लोगों को पशुपालन में उतना अधिक मुनाफा नहीं होता है, क्योंकि गाय-भैंस पौष्टिक आहार न मिलने की वजह से कम दूध देने लगती हैं। ऐसे में किसान को आर्थिक नुकसान होता है। लेकिन किसानों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे नीचे बताए गए तरीकों को अपना कर दूध का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। पशु एक्सपर्ट की माने तो इंसान की तरह गाय-भैंस को भी पौष्टिक और संतुलित आहार की जरूरत होती है। अगर उन्हें पोषण से युक्त आहार नहीं मिलता है, तो वे दूध देना कम कर देती हैं। साथ ही उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए किसानों को अपने पशुओं को हरा चारा खिलाना चाहिए।

कैसे करें बीज की बोवनी

अगर किसान मकचरी की खेती करना चाहते हैं, तो प्रति हेक्टेयर 40 किलोग्राम बीज की बुवाई करनी पड़ेगी। खास बात यह है कि इसकी बुवाई करने की विधि भी मक्के के समान ही है। यदि उर्वरक की बात करें तो 100 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में छिड़काव करें। खास बात यह है कि फसल बुआई के 2 से 3 माह बाद चारा कटाई के योग्य हो जाता है। एमपी। चरी की भांति इसकी भी दो से तीन कटाइयां की जा सकती हैं। इसकी उपज 600-800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है।

भैंस को क्या खिलाएं

हरे चारे की आवश्यकता पशु के शरीर भार, नस्ल और प्रकार पर निर्भर करती है। गाय का हरा चरा आप रोज 25 किलो दे सकते हैं। लेकिन सूखा चारा 8 किलो प्रतिदिन देना चाहिए। इसी तरह एक भैंस को रोज 30 किलो हरे चारे की जरूरत होती है, लेकिन वह सूखा चारा 10 किलो तक ही खा पाती है। अगर आप पशुपालन से अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो अपने दुधारू पशुओं को हमेशा हरा चारा खिलाएं। उसमें भी मकचरी हो तो और अच्छी बात है।

सब्जी की खेती ने बदल दी पहचान

गांव में 85 किसान उगा रहे ककड़ी-खीरा और सब्जियां

पूरे मध्यप्रदेश में कर रहे सप्लाई

गुना। जागत गांव हमार

जागत गांव हमार इस अंक में अपने पाठकों को बता रहा है सब्जियों की खेती करने वाले भटोदिया गांव की कहानी। भटोदिया गुना जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर है। इस गांव की पहचान सब्जी वाले गांव के नाम से है। यहां करीब 600 की आबादी है। 2014 से पहले यहां के किसान पारंपरिक खेती करते थे। गेहूं, सोयाबीन, चना आदि फसलें ही उगाई जाती थीं।2014 में गांव के नवजीवन लोधा शिवपुरी के एक किसान के साथ सब्जी उगाने की ट्रेनिंग लेने जबलपुर पहुंचे। वहां से लौटे, तो तीन बीघा में सब्जी उगाई। पहली ही बार में अच्छा मुनाफा हुआ। देखते ही देखते पूरा गांव उन्हें फॉलो करने लगा। आज गांव में लगभग 90 प्रतिशत किसान सब्जियां उगाते हैं। प्रदेश के कई जिलों में इसी गांव की सब्जियां पहुंचती हैं। केवल खाने के लिए गेहूं की खेती की जाती है। बाकी जमीन पर अब सब्जियों की पैदावार की जा रही है। आज यह गांव रोजाना डेढ़ से दो लाख रुपए की सब्जी मंडी में भेजता है। गांव के किसानों को मिला लें तो लगभग 200 बीघा में सब्जी उगाई जाती है। जिले के हर घर में इस गांव में उगी हुई सब्जियां पहुंच रही हैं। इसके अलावा राजस्थान के छबड़ा जिले सहित ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर और कई जिलों में सब्जियां पहुंचती हैं। जबटीम गांव में पहुंची तो कुछ किसान खेतों में ककड़ी की तुड़ाई कर रहे थे। हमारी मुलाकात रवि लोधा से हुई। उन्होंने बताया कि इस गांव में सीजन के हिसाब से अलग-अलग सब्जियों के साथ-साथ खीरा, ककड़ी जैसी सब्जियां भी उगाई जाती हैं। मैं अभी एक बीघा में ककड़ी की खेती कर रहा हूं। इसमें रोजाना 3 से 4 क्विंटल ककड़ी निकल जाती है। एक सीजन में सभी खर्चे काटकर दो लाख रुपए तक मुनाफा हो जाता है। उन्होंने बताया कि ककड़ी की खेती के लिए जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। फरवरी के पहले हफ्ते में खेत की जुताई की जाती है। इसके बाद मिट्टी को बारीक करने के लिए खेत में रोडर वेटर चलाया जाता है। फिर देसी खाद डालते हैं।

एक बीघा में 3-4 ट्रॉली डालते हैं खाद

एक बीघा में लगभग 3-4 ट्रॉली खाद डालते हैं। उसके बाद बेड तैयार किए जाते हैं। एक बेड की चौड़ाई करीब डेढ़ फीट होती है। लंबाई खेत के हिसाब से कितनी भी हो सकती है। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी डेढ़ फीट रखी जाती है। फिर बेड पर देसी खाद डाला जाता है। उसके बाद रासायनिक खाद डाला जाता है। बेड तैयार होने के बाद उस पर ड्रिप के लिए पाइप बिछाया जाता है। इसके बाद उस पर फरवरी के 20 तारीख के आसपास बीज डाल देते हैं।

एक बीघा में 50 हजार रुपए तक लागत

एक बीघा में ककड़ी उगाने के लिए खेत तैयार करने में करीब 10 हजार रुपए की लागत आती है। इसमें खेत तैयार करने से लेकर रख-रखाव, पानी, बिजली, खाद, रासायनिक खाद शामिल होता है। बीज की कीमत अलग होती है। ककड़ी के बीज की कीमत अलग-अलग आती है। जैसे, एक बीघा में करीब 100 ग्राम बीज लगता है। बीज की कीमत 500 रुपए प्रति 10 ग्राम है। इस हिसाब से एक बीघा में 5000 रुपए का बीज लगता है। खेत की तैयारी से लेकर उत्पादन होने तक करीब 45 से 50 हजार रुपए लागत लग जाती है।

ककड़ी की खेती के लिए जलवायु और मिट्टी

ककड़ी की खेती के लिए गर्म और शुष्क जलवायु अच्छी मानी जाती है। पौधे के अच्छे विकास के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान जरूरत होती है। ककड़ी की खेती बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इस तरह की मिट्टी में ककड़ी की फसल से अच्छी उपज मिलती है। ककड़ी की खेती के लिए ज्यादा अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए जलभराव जैसी समस्या से फसल को बचाने के लिए खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था जरूर करनी पड़ती है।

रोजाना 2 लाख की सब्जी की पैदावार

गांव के 90 प्रतिशत घरों से रोजाना लगभग डेढ़ से दो लाख रुपए की सब्जी मंडी में पहुंचती है। इस तरह हर महीने लगभग 50 लाख रुपए की सब्जियों की पैदावार यह गांव कर रहा है। सालाना पैदावार की बात करें, तो 5 करोड़ से ज्यादा की सब्जियां इस गांव में उगाई जा रही हैं। आज गांव में 90 प्रतिशत घर पक्के बने हैं। ग्रामीणों के जीवन मे काफी बदलाव आया है।

एक बीघा में 200 क्विंटल तक उत्पादन

किसान रवि लोधा बताते हैं कि बुआई के 45 से 60 दिन बाद ककड़ी के फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। एक सीजन में 200 से 250 क्विंटल तक की पैदावार हो जाती है। ये उपज खेती के तरीके, किस्म, उर्वरक, जलवायु और देखरेख पर निर्भर करती है। ककड़ी के फल जब हरे और मुलायम हों, तब तुड़ाई कर लें, क्योंकि ज्यादा देर से तुड़ाई करने पर फल कड़वे हो जाएंगे और बाजार में इसका उचित मूल्य नहीं मिलेगा।बाजार में ठीक भाव मिले, तो ककड़ी 20 रुपए प्रति किलो तक बिक जाती है। इस हिसाब से करीब सात हजार तक की उपज डेली बिकती है। सीजन की बात करें, तो दो महीने में करीब चार लाख तक की ककड़ी बिक जाती है। इसमें लागत, मजदूरी और मंडी तक उपज ले जाने का खर्चे काटकर एक सीजन में करीब दो लाख रुपए का मुनाफा हो जाता है।

महिलाओं की बढ़ रही आत्मनिर्भरता: अब तीन हजार से अधिक हो चुकीं लाभान्वित, विदेश भी जा रहे कुछ उत्पाद

सागर में महिलाएं बना रहीं गोबर से सुंदर घड़ियां और मोमेंटो

सागर। जागत गांव हमार

गाय के गोबर से कलात्मक वस्तुएं बनाकर सागर की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। गोबर से दीवाल पर टांगने वाली घड़ियां बनाई जा रही हैं। मोमेंटो बन रहे हैं। मालाएं बन रही हैं। इतना ही नहीं, सागर की 3000 से अधिक महिलाओं की आय का साधन बन गया है गाय का गोबर। इससे बनी कलात्मक वस्तुओं की बाजार में भी खूब मांग हो रही है। कुछ उत्पाद तो विदेश तक जा रहे हैं। सागर में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए यह एक तरह का अभियान ही है। महिलाएं औसतन तीन हजार रुपए प्रतिमाह और कुछ तो छह से दस हजार रुपए प्रतिमाह भी कमा रही हैं। इसी काम से जुड़ी आकांक्षा नामदेव ने बताया कि हमें गोबर से कलात्मक वस्तुएं बनाने की जानकारी मिली तो प्रशिक्षण लिया। अब हम लोग घड़ी और मोमेंटो बनाते हैं। इसके लिए हमें सामग्री मिल जाती है। हम घर पर ही अपने काम से समय निकालकर गोबर से कलात्मक वस्तुओं को बनाते हैं और फिर संस्था को दे देते हैं। शहर की एक समिति ने इन महिलाओं को जोड़े रखा है। समिति की अध्यक्ष सुनीता जैन ने बताया कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए यह पहल की गई है। अब तक तीन हजार से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। अब तक महिलाओं ने 1,500 घड़ियां, 8,000 मोमेंटो और 6,000 से अधिक माला बनाई हैं। देश-विदेश के बाजारों में यह उत्पाद भेजे जा रहे हैं। इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी हो रहा है।

कलात्मक उत्पाद

गौशाला से गोबर लिया जाता है और उसे सुखाया जाता है। उसके बाद मशीनों की मदद से उसे बारीक किया जाता है। आवश्यकतानुसार मिट्टी मिलाई जाती है। गोबल एवं अन्य जैविक सामग्री मिलाकर छह-छह किलो के पैकेट्स तैयार होते हैं। इन्हें ही महिलाओं को दिया जाता है। सांचे की मदद से निश्चित आकार दिया जाता है। सूखने के बाद कंडों की अच्छी से घिसाई और कटिंग होती है। इसके बाद गोंद और प्लाई की मदद से जोड़ा जाता है। रंग, कांच आदि का इस्तेमाल कर उसे सजाया जाता है। छह आकार की घड़ियां और कई आकार के मोमेंटो बनाए जा रहे हैं। इसमें कंप्यूटर की मदद से डिजाइन भी बनाए जाते हैं।

तीन से चार हजार प्रतिमाह कमाई

पूजा प्रजापति ने कहा कि मैं पढ़ाई करने के साथ ही गोबर के आइटम बना रही हूं। गोबर की घड़ियां, मोमेंटो बनाती हूं। रोज दो से तीन घंटे काम कर महीने के तीन-चार हजार रुपए कमा लेती हूं। इसी तरह आकांक्षा नामदेव ने कहा कि समिति से घर पर सामग्री दी जाती है। घर का काम करने के बाद वक्त मिलते ही कलात्मक वस्तुएं बनाती हूं। मैं भी तीन से चार हजार रुपए कमा लेती हूं।

खरगोन में पुलिस के साए में टोकन वितरण

कपास बीज के लिए हंगामा भीषण तपन!कतार में किसान

-टेंट-पानी की व्यवस्था नहीं,बोवनी नहीं हुई तो अगली फसल में पिछड़ेगी

खरगोन। जागत गांव हमार

उच्च गुणवत्ता के कपास उत्पादन के लिए प्रदेश और देश में पहचाने जाने वाले खरगोन जिले में कपास के बीज प्राप्त करने के लिए किसानों को घंटो मशक्कत करना पड़ रही है। बीटी काटन कपास बीज रासी 659 और आशा नुजिवुड के लिए किसान रात 4 बजे से कृषि मंडी में आकर कतार में लग रहे हैं। टोकन वितरण नहीं हुआ तो किसानों ने जमकर हंगामा किया। मंडी के सामने हाईवे पर रास्ताजाम भी कर दिया। अधिकारियों के आने के बाद टोकन वितरण शुरू किया तो किसान राजमार्ग से हटे। सुबह 5 बजे से किसान कृषि उपज मंडी पहुंचकर कतार में लग गए। लेकिन सुबह 11 बजे तक न टोकन वितरण शुरू हुआ न ही काउंटर खुला तो वे आक्रोशित हो गए। गुस्साए किसान मंडी गेट पहुंच गए जहां बीच सड़क धरना दे दिया। इससे आवाजाही बाधित हुई।

कृषि विभाग ने कुछ नहीं किया

मौके पर पहुंचे एसडीएम भास्कर गाचले, एएसपी टीएस बघेल व डीडीए एमएल चौहान ने किसानों को बीज उपलब्ध करवाने का भरोसा दिया। इसके बाद दोबारा किसान कतार में लगे। किसान बोंदरसिंह बड़ोले, त्रिलोक खरते का कहना है कि हर साल दोनों किस्म के बीज की मांग रहती है। इसके बावजूद कृषि विभाग ने अब तक कोई ठोस पहल नहीं की है। व्यापारी मनमानी कर रहे हैं।

जल्द ही समस्या दूर कर ली जाएगी

वर्तमान समय बोवनी का है, यदि समय पर बोवनी नहीं हुई तो अगली फसल में पिछड़ जाएंगे। किसान पिछले तीन दिन से 42 डिग्री तापमान में खुले आसमान के नीचे कतार लगा रहे हैं। छाया के साथ ही समय पर टोकन व्यवस्था नहीं होने से कृषि विभाग सहित शासन- प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। मामले में डीडीए का कहना है कि विशेष बीजों की मांग की जा रही है। कंपनी ने जितने बीज पैकेट भेजे हैं उतने वितरित करवाए रहे हैं। कंपनियों से बीज उपलब्धता बढ़ाने के लिए कहा है।

जबलपुर में चार अफसरों पर गिरी निलंबन की गाज

गेहूं खरीदी में करोड़ों का भ्रष्टाचार!

जबलपुर। निरीक्षण के दौरान चरगवां स्थित एक वेयर हाउस में सड़ा-घुना व पुराना गेहूं पाया गया। गेहूं खरीदी में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार मामले चार अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिरी है। जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना के अनुसार राघव वेयरहाउस चरगंवा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान पुराना, घुना हुआ और नॉन एफएक्यु गेहूं स्टैक्स लगाकर कर भंडारित किया जाना पाया गया। गेहूं सूखा भरतपुर सहकारी समिति द्वारा समर्थन मूल्य पर कथित किसानों से खरीदा गया था। कुल 212 किसानों से 25800 क्विंटल की खरीदी दर्ज की गई। उपार्जन मार्कफेड द्वारा लगभग 20,000 क्विंटल खरीदी की अनुमति दी गई थी। इसके आधार पर कुल भुगतान राशि 6.19 करोड़ के विरुद्ध 4.56 करोड़ का भुगतान हो चुका है। प्राथमिक जांच में कुल 13 स्टैक्स में से 2 स्टैक्स में अंदर की लेयर में पुराना, घुना हुआ और नॉन एफएक्यू गेहूं पाया गया है। अन्य स्टैक्स में भी खराब गेहूं भंडारित होने की आशंका है।

इन पर गिरी गाज

खरीदी घपले में समिति प्रबंधक राकेश नंदेसरिया, खरीदी केंद्र प्रभारी भूपेंद्र सिंह पटेल, अभिषेक दीक्षित वेयरहाउस संचालक, ऑपरेटर सुंजल जैन, सर्वेयर प्रवीण रजक और शुभम शर्मा की संलिप्तता प्रथम दृष्टया पाई गई है। इस घोटाले के मामले में नोडल अधिकारी रघुनाथ कुदौलिया सहकारिता निरीक्षक तथा जेएमओ भावना तिवारी एवं कुंजम सिंह राजपूत को निलंबित कर दिया गया था। वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की शाखा प्रबंधक प्रियंका पठारिया के निलंबन का प्रस्ताव विभागीय एमडी को भेजा गया था। उन्हें भी विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)